भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 707

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

कोयले की बढ़ती मांग

707. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन का संज्ञान लिया है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि 2030 में उच्च आर्थिक विकास दर और प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत को देखते हुए भारत में कोयले की खपत 1853 मिलियन टन (एमटी) तक बढ़ जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो देश में कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : रेलवे बोर्ड द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने कोयले की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए देश में घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन, ताकि कैप्टिव खानों को अंत्य उपयोग संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक उत्पादन का 50% तक बेचने की अनुमति मिल सके, एमडीओ मोड के माध्यम से उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकियों का बढ़ता उपयोग, नई परियोजनाएं और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार, तथा वाणिज्यिक खनन के लिए निजी कंपनियों/पीएसयू को कोयला ब्लॉकों की नीलामी शामिल हैं। वाणिज्यिक खनन के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति दी गई है।

(ii) कोल इंडिया लिमिटेड ने खानों (ब्राउनफील्ड परियोजनाओं) के विस्तार, नई खानों (ग्रीनफील्ड परियोजनाओं) को खोलने, अपनी यूजी और ओसी दोनों खानों के मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से अपने कोयला उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई है।

(iii) रेल मार्ग के माध्यम से अखिल भारतीय कोयला परिवहन रेल मंत्रालय का क्षेत्र है। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक 'लचीला' रेलवे प्रणाली बनाने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) तैयार की है। इसका उद्देश्य माल परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीति पहल दोनों के आधार पर कार्यनीति तैयार करना है। इसके अलावा मिशन 3000 मि.ट. को कोयले सहित माल ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि कार्यों की पहचान और प्राथमिकता देकर एनआरपी के उपरोक्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मध्यवर्ती मील का पत्थर दिया गया है।

भारतीय रेलवे ने देश में कोयला परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई पहलें की हैं और रेलवे उन मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2022-23 में सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 1.6 लाख करोड़ (बीई) थी, जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2.4 लाख करोड़ (बीई) हो गई है। इसी प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि का समर्थन करने के लिए क्षमता विस्तार और परिसंपत्ति आधुनिकीकरण के लिए चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.6 लाख करोड़ (बीई) के अब तक के सर्वाधिक पूंजीगत व्यय की योजना बनाई गई है।

कोयला निकासी अवसंरचना में सुधार के लिए भारतीय रेलवे की उपरोक्त पहलों/परियोजनाओं के अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड राज्य में ब्राउनफील्ड क्षेत्रों में अपनी विस्तार खनन परियोजनाओं और ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में नई खनन परियोजनाओं के लिए सात नई रेलवे लाइनों के निर्माण में लगभग 20000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह इसके कमान क्षेत्र के अंतर्गत नई रेलवे साइडिंग के निर्माण और पुरानी साइडिंग के नवीनीकरण और क्षमता वृद्धि के अतिरिक्त है।

****